



## Essay on 7<sup>th</sup> Pay Commission

### Key Points

#### **1. Introduction**

- 1) It gives recommendations regarding changes in salary structure of all civil and military divisions of government.
- 2) Setup in every 10 years.
- 3) Headed by justice A.K. Mathur.
- 4) Recommendations were implemented from January 1, 2016.
- 5) It's recommendations are very important for fighting inflation and supporting basic requirements for pensioners.

#### **2. Body**

- 1) Financial impact of implementing recommendations will be Rs 1.02 lakh crore.
- 2) 23.55 per cent increase in pay and allowances recommended.
- 3) Minimum pay fixed at Rs 18,000 per month
- 4) Commission recommends abolishing 52 allowances; another 36 allowances subsumed in existing allowances or in newly proposed allowances.
- 5) Recommendations will impact 47 lakh serving govt employees, 52 lakh pensioners, including defense personnel.
- 6) 6<sup>th</sup> Vs 7<sup>th</sup> : annual increment rate from 2.5 to 3%, performance pay. Increment in HRA.
- 7) Government had to release 0.7% of the GDP for this hefty expenditure.
- 8) It will widen fiscal deficit.
- 9) Some section of the armed and civil employees are not happy with current recommendations and their demands are under consideration.
- 10) The excess liquidity in the market will boost the economy and increase general expenditure.

### 3. Conclusion

- 1) Sectors like FMCG, electronics, real state, automobile etc will see more demand.
- 2) It will provide financial freedom to middle class families.
- 3) It will help in writing India's growth story.
- 4) Keeping aside the dissent among a small fraction, the recommendations of 7<sup>th</sup> pay commission will surely benefit the economy.

---

## सातवां वेतन आयोग पर निबंध

### 1. Introduction

- 1) यह सरकार के सभी नागरिक और सैन्य विभागों के वेतन संरचना में परिवर्तन के बारे में सिफारिशें प्रस्तुत करता है।
- 2) हर 10 वर्षों में संस्थापन
- 3) न्यायाधीश ए.के. माथुर के अधीन।
- 4) सिफारिश 1 जनवरी, 2016 से लागू की गई थी।
- 5) मुद्रास्फीति से लड़ने और पेंशनभोगी लोगों के लिए बुनियादी जरूरतों के लिए ये सिफारिशें बहुत महत्वपूर्ण हैं।

### 2. Body

- 1) सिफारिशों को लागू करने का वित्तीय प्रभाव 1.02 लाख करोड़ रुपये होगा।
- 2) 23.55 प्रतिशत वेतन और भत्तों में वृद्धि की सिफारिश की।
- 3) न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति महीने तय है
- 4) आयोग 52 भत्तों को खत्म करने की सिफारिश करता है; मौजूदा भत्ते में या नए प्रस्तावित भत्तों में 36 भत्ते शामिल हैं।

- 5) सिफारिशें 47 लाख सेवारत सरकारी कर्मचारी, 52 लाख पेंशनभोगी होंगे, जिनमें रक्षा कर्मी भी होंगे
- 6) 6 बनाम 7 : वार्षिक वेतन वृद्धि दर 2.5 से 3%, एचआरए में वृद्धि
- 7) इस व्यय के लिए सरकार को जीडीपी के 0.7% खर्च करना पड़ा।
- 8) यह राजकोषीय घाटे को बढ़ा देगा
- 9) सशस्त्र और नागरिक कर्मचारियों के कुछ खंड वर्तमान अनुशंसाओं से खुश नहीं हैं और उनकी मांगें विचाराधीन हैं।
- 10) बाजार में अतिरिक्त धन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा और सामान्य व्यय में वृद्धि करेगा।

### 3. Conclusion

- 1) एफएमसीजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, वास्तविक राज्य, ऑटोमोबाइल इत्यादि जैसे क्षेत्र अधिक मांग देखेंगे।
- 2) यह मध्यवर्गीय परिवारों को वित्तीय आजादी प्रदान करेगा।
- 3) 7 वीं वेतन आयोग की सिफारिशों से अर्थव्यवस्था को निश्चित रूप से लाभ होगा।
- 4) यह जीडीपी विकास में वृद्धि करेगा